स्थापना : 1997 संपर्क : 09869256875

प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित

• Website : www.railsamachar.com
• Website : www.railsamacharenglish.com
• Email : railwaysamachar@gmail.com

परिपूर्ण रेलवे समाचार

रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

वर्ष - 13 अंक - 311 | कल्याण (मुंबई), 16 से 30 अप्रैल 2015 | पेज-8 | मूल्य 5 रु.

जोनल महाप्रबंधकों को ही प्राथमिकता तय करने का अधिकार हो –श्रीधरन

दिल्ली : भारतीय रेल की रसातल में जा रही प्रशासनिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु ई. श्रीधरन ने सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रेलवे के जिम्मेदार और वरिष्ठ जोनल अधिकारियों को पर्याप्त अधिकार संपन्न बनाया जाना चाहिए, ताकि वे यथासमय रेलवे के हित में तुरंत निर्णय ले सकें. विकेंद्रीकरण का सुझाव देते हुए उन्होंने अपनी

रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु को रिपोर्ट सौंपते हुए ई. श्रीधरन

नीति निर्धारण और मॉनिटरिंग तक ही सीमित होनी चाहिए रेलवे बोर्ड की भूमिका

रिपोर्ट में कहा है कि रेलवे बोर्ड को खरीदारी के काम से मुक्त किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने जोनल स्तर पर अधिकारियों की बनाई जाने वाली निगेटिव लिस्ट को भी खत्म करने का सुझाव दिया है. निगेटिव लिस्ट उसे कहा जाता है, जिसमें यह जानकारी दी जाती है, कि रेलवे के जोनल अधिकारी क्या-क्या फैसले नहीं ले सकते हैं. श्रीधरन कमेटी ने रेल शेष पेज 7 पर...

भारतीय रेल के 162 साल

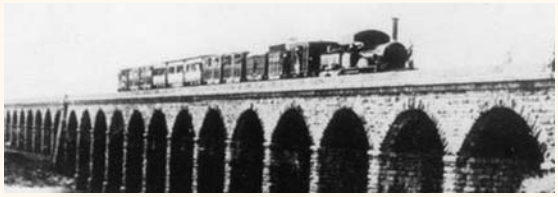

दिल्ली : कम या लंबी दूरी के यातायात के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन के रूप में देश की जीवनरेखा बन चुकी भारतीय रेल ने 16 अप्रैल 2015 को भारत में अपनी सेवा के 162 साल पूरे कर लिए हैं. 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली यात्री गाड़ी बोरीबंदर (अब शिवाजी छत्रपति टर्मिनस) और ठाणे के बीच चली थी, जिसे रेलवे के जन्मदिन के तौर पर याद किया जाता है. उल्लेखनीय है कि हर साल 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक रेल सप्ताह के तौर पर भारतीय रेल द्वारा अपनी स्थापना को एक जश्न के रूप में मनाया जाता है. ग्रेट इंडियन पेनिससुला रेलवे (जीआईपीआर) द्वारा चलाई गई 16 डिब्बों की पहली रेलगाड़ी में साहिब, सिंध और सुल्तान नामक तीन इंजन लगाए गए थे. इस पहली गाड़ी ने 57 मिनट में 21 मील की दूरी तय की थी. रेल मंत्रालय ने इस दिन पुरानी, ऐतिहासिक और भावपूर्ण तस्वीरों में 'भारतीय रेलवे के 162 साल' लिखकर और इन्हें सोशल मीडिया पर साझा करके इस अवसर को यादगार बना दिया.

दंडित किसे किया जाए?

सुरेश त्रिपाठी

दूर-दराज से सुबह के समय मुंबई आने वाली गाड़ियों के हजारों रेलयात्री प्रतिदिन जो यातना भुगत रहे हैं, उसके लिए वास्तव में मुंबई मंडल, मध्य रेल का अनुभवहीन अथवा नियंत्रणहीन स्टाफ जिम्मेदार है. यह यात्री घंटों तक लूप लाइन में खड़ी कर दी जाने वाली गाड़ियों के कारण अपना बहुमूल्य समय तो खोते ही हैं, बल्कि उनमें से सैकड़ों यात्रियों को लाखों का नुकसान भी उठाना पड़ता है और कईयों की तो जिंदगी ही बरबाद हो जाती है, क्योंकि वह निर्धारित समय पर अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाते हैं. मुंबई मंडल के अप नार्थ ईस्ट सेक्शन में चर्किंग टाइम टेबल का उपयोग सिर्फ गाड़ी के विलंब का आकलन करने हेतु होता है. पचास प्रतिशत गाड़ियां अपने निर्धारित समय से नहीं चलतीं, उसमें भी 80 प्रतिशत गाड़ियों को लेट करने में मुंबई मंडल की अपनी खास भूमिका होती है. मुंबई मंडल की पंक्चुअलिटी मीटिंग्स गाड़ियों को निर्धारित समय पर चलाने के लिए नहीं, बल्कि शायद इसलिए की जाती हैं कि उनको और विलंबित कैसे किया जाए? कितनी ही गाड़ियां इगतपुरी में अपने निर्धारित समय से 25-30 मिनट पहले आने के बावजूद अपने गंतव्य पर लेट पहुंचती हैं. कुर्ला टर्मिनस की गाड़ी के घाटकोपर पहुंचते ही उसका पंक्चुअलिटी में 'अरावयल' दर्ज कर लिया जाता है. ऐसी ही सीएसटी बाउंड गाड़ी का भायखला पहुंचते ही 'अरायवल' चढ़ा लिया जाता है, जबकि कुर्ला टर्मिनस, जो कि घाटकोपर से मात्र 1 किमी. दूर है, पहुंचने में किसी भी गाड़ी को 45 से 75 मिनट लग जाते हैं. इसी तरह मझगांव से सीएसटी के बीच भरपूर समय व्यर्थ किया जाता है. मुंबई मंडल के अधिकांश स्टाफ को इगतपुरी में किसी एक गाड़ी के लिए बुक किया जाता है, महार वह काम किसी और ही गाड़ी में करता है. अधिकांशतः जिस गाड़ी की बुकिंग होती है, वह दो घंटे तक आती ही नहीं. यही वास्तविकता है. मनमाड़ से तो गाड़ियां सही समय पर निकल जाती हैं, परंतु मुंबई मंडल में घुसते ही 'नो रूम' और प्राथमिकता (प्रायरटी) की गाड़ियों के आदेश के चलते उनको घंटों लूप में खड़ा करके विलंबित किया जाता है. यह गाड़ियां जब मुंबई मंडल में प्रवेश करती हैं, तो जैसे सिर मुंडते ओले पड़ते हैं, कुछ वैसी ही स्थिति होती है. यहां पीक आवर्स के चलते खर्डी से लेकर खड़वली और वाशिंद तक सारे लूप यात्री गाड़ियों से भरे पड़े रहते हैं. जो गाड़ी ठाणे तक पहुंच गई, उसको सांप-सीढ़ी का खेल खेलाते हुए कभी मेन लाइन, तो कभी 5वीं-6ठी लाइन पर चलाया जाता है. शेष पेज 4 पर...

रेलमंत्री की सख्ती से आना शुरू हुआ गाड़ियों के सही समयपालन का परिणाम

मुंबई : भारतीय रेल की ट्रेनों की लेटलतीफी से परेशान और आजिज आ चुके रेल यात्रियों ने पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री कार्यालय तक इसकी शिकायत पहुंचाई और इस बारे में जब खुद प्रधानमंत्री ने रेलमंत्री सुरेश प्रभु से सवाल कर दिया था, तो रेलवे बोर्ड से लेकर जोनल रेलों तक भारी सक्रियता देखी गई थी. रेलवे बोर्ड सहित अब खुद रेलमंत्री ने भी अब प्रतिदिन हर जोन से गाड़ियों की टाइमिंग की रिपोर्ट मांगनी शुरू की है.

रेलमंत्री सुरेश प्रभु

इस संबंध में मेंबर ट्रैफिक, रेलवे बोर्ड द्वारा सख्त हिदायत भी जारी की गई है कि गाड़ियों के संचालन का सही समय ही दर्ज किया जाए, अन्यथा जोन के मुख्य यात्री यातायात प्रबंधक, मुख्य परिचालन प्रबंधक और मंडल स्तर पर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, मंडल परिचालन प्रबंधक और सहायक परिचालन प्रबंधक का तबादला सीधे दूसरे जोन किया जाएगा. अब यदि कोई गाड़ी अपने गंतव्य पर देरी से पहुंचती है, तो इसका पता लगाने के लिए सीधे लोको पायलट से पूछताछ की जा रही है. रेलमंत्री और मेंबर ट्रैफिक शेष पेज 7 पर...

रेलवे बोर्ड में बड़े पैमाने पर संभावित तबादलों से हड़कम्प

दिल्ली : रेलवे की कार्य प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की रेलमंत्री सुरेश प्रभु की पहल अब कुछ-कुछ अपना रंग दिखाने लगी है. पूर्व सीएजी विनोद राय की सिफारिश पर रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड में एक ही पद और एक ही निदेशालय में लम्बे अर्से से जमे बैठे रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला शुरू हो गया है. अब तक करीब 25 कार्यालय सहायकों और करीब 15

विनोद राय समिति की सिफारिशों को एकमुश्त लागू किया जाए

सेक्शन ऑफिसरों के पदों में फेरबदल किया गया है. इस कार्रवाई से रेलवे बोर्ड में एक पद पर लम्बे समय से पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों में जबरदस्त हड़कम्प मचा हुआ है.

उल्लेखनीय है कि रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की कार्य-प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) विनोद राय की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया था. इस समिति ने मार्च के अंतिम सप्ताह में अपनी पहली सिफारिश में कहा था कि रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में पांच और दस वर्षों से लगातार एक ही पद और एक ही निदेशालय में शेष पेज 7 पर...

पू.म.रे. का सौ मिलियन टन क्लब में शामिल होना गौरवपूर्ण -ए.के. मित्तल

हाजीपुर : पूर्व मध्य रेलवे द्वारा श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल, पटना में 10 अप्रैल को 60वें रेल सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया. समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महाप्रबंधक ए. के. मित्तल एवं पू.म.रे. महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष श्रीमती मनु मित्तल ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारम्भ किया. इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक दीपक दवे एवं महिला कल्याण संगठन की उपाध्यक्ष श्रीमती शुभदा दवे भी उपस्थित थीं. इस मौके पर महाप्रबंधक ए. के. मित्तल ने वर्ष 2014-15 में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए कुल 366 रेलकर्मियों को व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए. इसके अलावा 10 समूह पुरस्कार, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य हेतु विभागों/मण्डलों के मध्य दक्षता एवं सर्वांगीण दक्षता शील्ड भी प्रदान की गई.

पूर्व मध्य रेल द्वारा 60वें रेल सप्ताह समारोह का आयोजन

धनबाद एवं मुगलसराय मंडल को मिली समग्र दाता शील्ड

इस अवसर पर वाणिज्यिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए महाप्रबंधक ने कहा कि पूर्व मध्य रेल ने भारतीय रेल के 100 मिलियन टन लदान एवं 10,000 करोड़ सकल आय प्राप्त करने वाले रेलों के क्लब में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है. वित्तीय वर्ष 2013-14 में 106.04 मिलियन टन लदान कर पूर्व मध्य रेल ने कीर्तिमान स्थापित किया था. वित्तीय वर्ष 2014-15 में वृद्धि का क्रम जारी रखते हुए कुल 107.48 मिलियन टन माल लदान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.36 प्रतिशत ज्यादा है. इस दौरान पू.म.रे. ने 11079 करोड़ रूपये की सकल आरंभिक आय अर्जित की है, जो इसके पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 7.65 प्रतिशत ज्यादा है.

उन्होंने कहा कि पू.म.रे. के परिचालन औसत, जो कि हमारी कार्यकुशलता का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है, में पर्याप्त सुधार हुआ है. रेलकर्मियों के योगदान के फलस्वरूप प्राप्त उपलब्धियों पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालते हुए महाप्रबंधक ने वर्ष 2014-15 में पू.म.रे. द्वारा चलाई गई नई गाड़ियों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि नई परियोजनाएं, नये आयामों का सृजन करती हैं. हम अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को काफी सुदृढ़ और विस्तृत कर रहे हैं, जिससे भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं तथा चुनौतियों को पूरा किया जा सके.

महाप्रबंधक ने रेलकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे बोर्ड ने पू.म.रे. को वर्ष 2015-16 में कई चुनौतीपूर्ण लक्ष्य प्रदान किए गए हैं. पूरा विश्वास है कि हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे. इसके पूर्व मुख्य कार्मिक अधिकारी सुशांत झा ने 60वें रेल सप्ताह में आए सभी रेल कर्मचारी एवं रेल अधिकारियों का स्वागत करते हुए रेलकर्मियों के लिए इसे काफी महत्वपूर्ण दिन बताया. महाप्रबंधक द्वारा इस मौके पर समग्र क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य दक्षता के लिए 2014-15 की महाप्रबंधक शील्ड संयुक्त रूप से धनबाद एवं मुगलसराय मंडल को प्रदान की गई, जबकि उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए महाप्रबंधक का रनर्स अप कप सोनपुर एवं दानापुर मंडल को मिला. दानापुर मण्डल को राजभाषा अंतरमण्डलीय दक्षता शील्ड तथा रनर्स अप कप समस्तीपुर मण्डल को प्रदान किया गया.

सिग्नल दक्षता के लिए संयुक्त रूप से दानापुर एवं मुगलसराय मण्डल को, परिचालन दक्षता के लिए धनबाद और मुगलसराय मण्डल, चिकित्सा दक्षता के लिए केन्द्रीय चिकित्सालय/पटना एवं मंडल चिकित्सालय/मुगलसराय को, संरक्षा शील्ड मुगलसराय मंडल को, इंजीनियरिंग दक्षता शील्ड धनबाद मंडल को प्रदान की गई. इसके साथ ही लेखा दक्षता शील्ड मुगलसराय मंडल तथा सामान्य विद्युत दक्षता शील्ड धनबाद मंडल को मिली है. टिकट चेकिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं वाणिज्य दक्षता शील्ड के लिए सोनपुर एवं समस्तीपुर मंडल को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया. कार्यक्रम के प्रारंभ में पूर्व मध्य रेल के कलाकारों द्वारा भव्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया.

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक/दानापुर एन. के. गुप्ता, मंडल रेल प्रबंधक/समस्तीपुर सुधांशु शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक/सोनपुर राजेश तिवारी, मंडल रेल प्रबंधक/मुगलसराय विद्याभूषण एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद एच. के. रघु सहित मुख्यालय एवं पांचों मण्डलों से आए अधिकारी, रेलकर्मी एवं महिला कल्याण संगठन की सदस्यायें भी उपस्थित थीं.

सैकड़ों यात्रियों की जान बचाने वाले लोको पायलट सुरेंद्र शर्मा जीएम अवार्ड से सम्मानित

पुणे से सीएसटी ट्रेन नं. 17412 अप महालक्ष्मी एक्सपेस (लोको नं. 21877) पर 8 अगस्त 2014 को लोको पायलट सुरेंद्र शर्मा कार्य कर रहे थे. भीषण बारिश तथा रात के 4.45 बजे गाड़ी को मंकी हिल केबिन से मिडिल लाइन पर डायवर्ट किया गया. ठाकुरवाड़ी केबिन के काफी पहले किमी 116/13 पर, जहां कि सामान्य गति से जाना था, करीब 2.5 से 3 टन की चट्टान रेल लाइन के बीचों बीच पड़ी थी. चालक श्री शर्मा ने तुरंत आपातकालीन ब्रेक लगा दिए. गाड़ी खड़ी होते-होते भी उक्त चट्टान से टकरा गई. पर गनीमत थी कि केवल इंजन का केटल गार्ड ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ मगर दैवयोग से भयंकर डिरेलमेंट तथा सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई. अब श्री शर्मा के सामने सवाल यह था कि इतनी विशाल चट्टान ट्रैक से कैसे हटाई जाए? उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से सभी संबंधित लोगों और अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी. उसी समय वहां एक पेट्रोलमैन (गैंग मैन) आया. उसने तत्परता दिखाते हुए 15 मिनट के अंदर अपने और 3-4 साथियों को बुलाया, पर इतने लोगों से वह चट्टान कहां सरकने वाली थी. अंततः लोको पायलट सुरेंद्र शर्मा ने अपनी सूझबूझ से सहायक चालक सरोज सिंह तथा चारों गैंगमैनों की सहायता से किसी तरह उस विशाल चट्टान को लाइन के बाहर धीरे-धीरे सरका डाला. इस बीच कोई अन्य सहायता न मिलने तथा गैंगमैनों के समर्पण से

प्रभावित होकर श्री शर्मा ने गैंगमैनों के काफी मना करने के बावजूद उनको प्रोत्साहन स्वरूप 200 रु. भी दिए. इस सब कार्य में करीब एक घंटे का विलंब हुआ.

इतने भयंकर तरीके से डैमेज हुए और करीब 5-6 क्विंटल वजनी केटल गार्ड, जो यदि ट्रैक पर गिर जाता तो गाड़ी का डिरेलमेंट निश्चित था. यदि गाड़ी को वहीं खड़ी रखा, तो सारा मूवमेंट बंद हो जाता. तब श्री शर्मा ने सीनियर डीईई (ऑपरेशंस) को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराकर गाड़ी को उसी स्थिति में आगे ले जाने का निर्णय लिया. पूरे मार्ग में उन्होंने अपने वर्षों के कार्यानुभव का सम्पूर्ण उपयोग करते हुए, कि कहां एक्स-ओवर पर धक्का लगेगा, ट्रैक पर कहां झटका लगता है, कहां गाड़ी उछलती है, हिचकोले खाती है, इन सबको ध्यान में रखते हुए उस जगह गति को अत्यंत धीमी कर करके कुल 50-55 किमी. की गति से पूरे आत्मविश्वास तथा ईश्वर पर आस्था रख सुरक्षित तरीके से 116 किमी. दूर (मुंबई) तक गाड़ी को अपने गंतव्य तक पहुंचाकर ईश्वर का धन्यवाद अदा किया. लोको का कैटल गार्ड इतना डैमेज था कि सीएसटी प्लेटफार्म के बाजू में लगे ट्रिप शेड तक लोको को ले जाने तक की हिम्मत कोई नहीं कर पाया था. 116 किमी. इतनी सावधानी के साथ मात्र 10 मिनट के विलंब से सुरेंद्र शर्मा ने गाड़ी को गंतव्य तक पहुंचाकर सभी को आश्चर्य में डाल दिया. इस हेतु श्री शर्मा को इस साल के रेल सप्ताह समारोह में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुनील कुमार सूद ने महाप्रबंधक अवार्ड से पुरस्कृत किया है.

इसके अलावा 6 फरवरी 2015 को ट्रेन नं. 12102 अप ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस (लोको नं. 22529) में रात 3.20 बजे घुप्प अंधेरे में इगतपुरी में गाड़ी का चार्ज लेने के दौरान लोको पायलट सुरेंद्र शर्मा ने इंजन की कपलिंग को बेहद आश्चर्यजनक स्थिति में टूटा पाया. उसमें करीब 6-7 इंच का गैप था. उन्होंने तुरंत सभी संबंधितों को सूचित किया. इंजन परीक्षक ने आकर कहा कि लोको बदलना होगा. यानी इस काम में कम से कम एक घंटे का विलंब होना निश्चित था. इस पर सुरेंद्र शर्मा ने अपने अनुभव तथा तात्कालिक सूझबूझ दिखाते हुए इंजन परीक्षक को सलाह दी कि एक कपलिंग मेरे इंजन में है. हम इंजन को गाड़ी से अलग करके प्रयास करते हैं कि यदि टूटी कपलिंग निकालकर उपलब्ध कपलिंग को वहां फिट कर सकें तो विलंब बच जाएगा. ऐसा ही किया गया. प्रयोग सफल रहा और केवल 25 मिनट में गाड़ी पुनः तैयार कर रवाना कर दी गई. जब संबंधित अधिकारियों ने विशेष तौर पर मध्य रेल के प्रमुख मुख्य इंजीनियर (विद्युत) जी. आर. अग्रवाल ने स्वयं उसका निरीक्षण किया, तो वह हतप्रभ रह गए. यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर उन्होंने चालक तथा सहायक चालक की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए दोनों को उत्तम कार्य निष्पादन का प्रमाण पत्र दिया. इससे जाहिर है कि चालक की एक सूझबूझ से रेलवे को करोड़ों का नुकसान टाला जा सकता है.

दमदम को 'बेस्ट मेनटेन स्टेशन' अवार्ड

कोलकाता : 60वें रेल सप्ताह के अवसर पर मेट्रो रेलवे के बेलगछिया ऑडिटोरियम में 15 अप्रैल को आयोजित समारोह में महाप्रबंधक श्री राधेश्याम ने बेहतर रख-रखाव के लिए 'बेस्ट मेनटेन स्टेशन' का अवार्ड दमदम मेट्रो स्टेशन को प्रदान किया. इस अवसर पर महाप्रबंधक ने 75 व्यक्तिगत और 71 समूह पुरस्कार मेट्रो रेलवे के विभिन्न रेलकर्मियों और अधिकारियों को प्रदान किया. उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय सेवाओं के लिए प्रदान किए इन पुरस्कारों में नकद राशि सहित पदक और योग्य गुणवत्ता प्रमाण-पत्र शामिल है.

वर्ष 2014-15 उत्तर रेलवे के लिए उपलब्धियों भरा रहा

दिल्ली : 16 अप्रैल, 1853 को बोरीबंदर से ठाणे के बीच भारत में चली पहली रेलगाड़ी की स्मृति में भारतीय रेल में इस दिन को प्रत्येक वर्ष रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है. इसी भावना से उत्तर रेलवे द्वारा इस वर्ष 10 अप्रैल से 16 अप्रैल 2015 तक 60वां रेल सप्ताह मनाया गया. इन्हीं आयोजनों के मद्देनज़र शुक्रवार, 17 अप्रैल को उत्तर रेलवे द्वारा रेल सप्ताह समापन समारोह का आयोजन नयी दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे, मुख्यालय, बड़ौदा हाउस में किया गया. महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे ए. के. पुठिया ने समारोह की अध्यक्षता की. इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक एस. के. पाठक, सभी विभाग प्रमुख और अन्य वरिष्ठ रेलवे अधिकारीगण तथा उत्तर रेलवे के कर्मचारी, यूनियन, एसोसिएशन, फेडरेशन के सदस्य, उत्तर रेलवे महिला कल्याण

उत्तर रेलवे द्वारा 60वें रेल सप्ताह का आयोजन

संगठन की अध्यक्ष श्रीमती माधुरी पुठिया तथा अन्य सदस्याएं भी उपस्थित थीं.

इस अवसर पर बोलते हुए महाप्रबंधक श्री पुठिया ने उत्तर रेलवे के प्रमुख कार्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति की सराहना की. उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 उत्तर रेलवे के लिए बहुत उपलब्धियों भरा रहा. मालभाड़ा क्षेत्र में फरवरी 2015 तक 7591.29 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित किया गया, जो कि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि से 14.72 प्रतिशत अधिक है. निरन्तर प्रयासों और मालभाड़ा प्रोत्साहन योजनाओं से उत्तर रेलवे द्वारा फरवरी 2015 तक 54.90 मिलियन टन का राजस्व लदान किया गया, जो कि

पिछले वर्ष की इसी अवधि में 53.37 मिलियन टन था. इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी. मूल यात्री आय में फरवरी 2015 तक 7125.11 करोड़ रु. की उल्लेखनीय आय दर्ज की गयी. यह पिछले वर्ष की इसी अवधि से 13.09 प्रतिशत अधिक है. उत्तर रेलवे द्वारा प्राप्त शीर्ष उपलब्धियों में 4 जुलाई, 2014 को 25.6 किमी. लम्बी ऊधमपुर - श्री माता वैष्णों देवी कटरा रेल लाइन का शुभारम्भ शामिल है. अब माता वैष्णों देवी कटरा तक 6 जोड़ी डीईएमयू रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं. अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियों में विद्युतीकरण के विस्तार के अन्तर्गत पठानकोट - जम्मूतवी (100.6 मार्ग किमी.) और खुर्जा - मेरठ सिटी (87.4 मार्ग किमी.) रेल मार्ग का विद्युतीकरण, खान आलमपुरा में नए विद्युत लोको शेड के पहले चरण का कार्य पूरा करना शामिल है.

वर्ष 2014-15 में उत्तर रेलवे द्वारा उपलब्धियों का महत्वपूर्ण अध्याय रचा गया. रेल यात्रियों की सुविधाओं में यथासम्भव विस्तार करके मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से रेलवे पूछताछ की नई सुविधा, नयी पीढ़ी की ई-टिकटिंग प्रणाली, कैश-ऑन-डिलिवरी योजनाएं, गो-इण्डिया स्मार्ट कार्ड, ई-खानपान योजना इत्यादि के माध्यम से टिकट खरीदना सुगम हुआ है. ऑन लाइन रेल टिकट बुकिंग सुविधा ने ई-शासन की सफलता सुनिश्चित की है. दूरभाष संख्या-139 पर सुबह जगाने और गंतव्य पर पहुँचने के सम्बन्ध में अलार्म सेवा की पायलट परियोजना के रूप में शुरूआत की गयी है. इसके अलावा रेल यात्री शिकायत 138 तथा सुरक्षा हैल्प लाइन शॉर्ट-कोड़ नं.-182 भी शुरू की गयी है. समारोह का शुभारम्भ उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ए. के. पुठिया द्वारा उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करने वाले 200 रेलवे कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के साथ हुआ. पांच समूह पुरस्कार और 43 शील्डें कार्य-निष्पादन के आधार पर महाप्रबंधक द्वारा प्रदान की गयी. दिल्ली मण्डल को महाप्रबंधक उत्कृष्टता शील्ड दी गयी तथा सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य निष्पादन के आधार पर अम्बाला मण्डल को सर्वश्रेष्ठ मण्डल चुना गया.

हाल ही में गुवाहाटी, असम में आयोजित रेल सप्ताह के दौरान उत्तर रेलवे को संरक्षा शील्ड तथा लेवल क्रॉसिंग, आरओबी/आरयूबी निर्माण कार्य के लिए शील्ड प्रदान की गयीं. इसी समारोह में उत्तर रेलवे के साथ हैल्थ केयर शील्ड पूर्व रेलवे एवं दक्षिण रेलवे को संयुक्त रूप से प्रदान की गयी. महाप्रबंधक ने उत्तर रेलवे के कर्मचारियों द्वारा उत्साह, निष्ठा और लगन के साथ की गयी सेवाओं पर संतोष जाहिर किया और आने वाले वर्षों में लक्ष्यों की नयी ऊँचाईयों को हासिल करने के लिए उनको प्रेरणा भी दी.

एसएसई सुधाकर एस. येंकर को महाप्रबंधक पुरस्कार

बडनेरा : निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बडनेरा - वनगांव सेक्शन के बीच ओएचई कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने और बडनेरा यार्ड में एक अत्यंत दुरूह टर्नआउट को हटाकर गति अवरोध दूर करने के समर्पित और सराहनीय कार्य के लिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर (एसएसई) सुधाकर एस. येंकर को 10 अप्रैल को सीएसटी ऑडिटोरियम में आयोजित 60वें रेल सप्ताह समारोह के अवसर पर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुनील कुमार सूद ने महाप्रबंधक अवार्ड, नकद राशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है. 13 साल बतौर एसएसई काम कर चुके श्री येंकर के काम की सराहना सीआरएस/सेंट्रल सर्किल ने भी की है और उनके सेक्शन को सबसे बेहतर रख-रखाव वाला सेक्शन कहा है. बडनेरा यार्ड के आधुनिकीकरण के तहत उन्होंने एक जटिल और शार्प कर्व वाले टर्नआउट को हटाया, जिससे वहां लम्बे समय से लगे स्थाई गति अवरोध को समाप्त किए जाने और गाड़ियों की गति बढ़ाने में मध्य रेलवे को पर्याप्त सफलता मिली है.

दिल्ली : वर्ष 2014-15 के दौरान बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए उत्तर रेलवे को तीन समग्र दक्षता शील्ड प्राप्त हुई हैं. यह शील्ड्स उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री ए. के. पुठिया को 13 अप्रैल को गुवाहाटी में आयोजित 60वें राष्ट्रीय रेल पुरस्कार वितरण समारोह-2015 के अवसर पर रेलमंत्री श्री सुरेश प्रभु ने प्रदान कीं. उत्तर रेलवे ने सुरक्षा शील्ड और लेवल क्रासिंग एवं रोड ओवर/अंडर ब्रिज सेफ्टी शील्ड प्राप्त हुई, जबकि कॉम्प्रेहेंसिव हेल्थ केयर शील्ड उत्तर रेलवे सहित पूर्व रेलवे एवं दक्षिण रेलवे को संयुक्त रूप से मिली है.

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आरपीएफ एसोसिएशन की गुवाहाटी में हाल ही में संपन्न सर्वसाधारण जोनल वार्षिक सभा और कार्यकारिणी मीटिंग का उद्घाटन करते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री निर्मल सिंह. उनके साथ हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आरपीएफ एसोसिएशन के महामंत्री बिमल दास एवं अन्य पदाधिकारीगण.

पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ आलोक कुमार सिंह पुरस्कृत

गोरखपुर : गुवाहाटी में रविवार, 12 अप्रैल को आयोजित '60वें राष्ट्र स्तरीय रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह-2015' में रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) आलोक कुमार सिंह को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया. रेलमंत्री श्री प्रभु ने सीपीआरओ आलोक सिंह को प्रशस्ति पत्र, पदक एवं नकद राशि प्रदान करके सम्मानित किया. समारोह में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ए. के. मितल, पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ रेल अधिकारी और

पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ आलोक कुमार सिंह को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कृत करते हुए रेलमंत्री सुरेश प्रभु. मंच पर उनके साथ हैं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा और मेंबर इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड वी. के. गुप्ता.

कर्मचारी उपस्थित थे. इस रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह में सराहनीय सेवाओं के लिए भारतीय रेल स्तर पर कुल 151 रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्य के प्रति अनुकरणीय समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए पुरस्कृत किया गया. पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ को यात्रियों को संरक्षा, सुरक्षा एवं सतर्कता संबंधी विषयों पर जागरूक करने के लिए प्रभावी अभियान चलाने तथा रेलगाड़ियों के परिचालन की सूचनाएं, खानपान सेवा एवं रेलवे की अन्य योजनाओं की सूचना तत्परतापूर्वक प्रसारित कराने पर पुरस्कृत किया गया है.

दंडित किसे किया जाए?

पेज 1 से आगे...

यानी सुबह के समय यात्रियों का ट्रेन से मुंबई पहुंचना किसी अभिशाप से कम नहीं होता है. इससे तो अच्छी पूर्व में चलने वाली जानवरों को ले जाने वाली मालगाड़ियां ही थीं, जिनको पानी आदि की सुविधा देखकर कहीं भी खड़ा कर दिया जाता था.

परंतु आज स्थिति यह है कि मनुष्यों को ले जाने वाली गाड़ियां, जिनमें बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिलाएं, गंभीर बीमारी का इलाज करवाने मुंबई आने वाले मरीज, एडमीशन, इंटरव्यू के लिए आने वाले छात्र, टेंडर के लिए आने वाले लोग, कोई संगोष्ठी-समारोह हेतु, तो कोई अंतिम सांसें गिन रहे अपने नाते-रिश्तेदार आदि से मिलने आने वालों के साथ मुंबई मंडल रेल प्रशासन का व्यवहार इस कदर अमानवीय होता है कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक शायद कोई अपने शत्रु देशों के साथ भी न करता होगा. घंटों ऐसे लूप में खड़ी गाड़ियां जहां न पानी मिले और न ही बिस्किट, चाय, नाश्ता, खाना. गंतव्य पर पहुंचने की प्रसन्नता ऐसी मायूसी में बदल जाती है कि 40-50 घंटे के सफर में जो दर्द न मिला हो, वह यातना इस बचे 30-40 मिनट के सफर में भोगता है. लूप मे कड़ी गाड़ियों के परेशान लोग चाय-पानी या नास्ते के लिए नीचे उतरते हैं और प्रति दिन काल के ग्रास बन रहे हैं. भारत में इससे बड़ा आतंकवाद कहीं नहीं होगा. संपूर्ण भारत में आतंक से होने वाली हत्याओं से कई गुना ज्यादा व्यक्ति यहां लूप में खड़ी गाड़ियों के दूसरी लाइन से गुजरने वाली गाड़ियों से मर-कट रहे हैं.

लोकल चलने वाली गाड़ियों को लाइन क्लीयर मिलती है मगर यही लाइन दूर से आने वाली गाड़ियों को नहीं मिलती, जबकि ये सभी गाड़ियां एक ही गति से चलती हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकल चलने वाली गाड़ियों के यात्री सम्बंधित अधिकारियों के चैम्बर्स में घुसकर हाथ-पैर चलाते हुए उन्हें रेल परिचालन की असली परिभाषा गाली-गलौज वाली भाषा में समझाने और उनके चैम्बर का नक्शा बदलने में सक्षम होते हैं. यह तोडफ़ोड़ तो रोज ही हो जा सकती है, क्योंकि इससे 1000 रु. के नुकसान को डेढ़-दो लाख का बताकर सरकारी राजस्व को चूना लगाना जारी रखा जा सकता है, मगर सम्बंधित अधिकारियों को रोज-रोज की यह गाली-गलौज और हाथापाई थोड़ी बुरी लगती है. इसलिए लोकल वालों की गाड़ियों को लाइन क्लीयर दे दी जाती है. बाहर से आने वाले लोग ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें भीड़ का समर्थन भी नहीं मिलता है, तो वह कहां जाएं और किससे लड़ें? वे अपनी परेशानी से ही दुखी रहते हैं. तथापि साल-छह महीने में जब कभी वे भी एकाध बार आक्रमक हो जाते हैं, तो 15 सेकंड में उस ट्रेन को सिग्नल मिल जाता है. ऐसा लगता है कि यहां लाइन क्लीयर की नहीं, बेइज्जती की समस्या है. यात्रियों के टिकट का पर्याप्त उपयोग और उनके पैसे/किराए की भरपाई तो उन्हें उनके गंतव्य यानी कुर्ला, दादर, सीएसटी तक पहुंचाकर ही की जा सकती है. परंतु प्रतिदिन अनेकों गाड़ियां घंटों लूप में लेट करने के बावजूद कम से कम तीन गाड़ियां कल्याण, ठाणे या दादर में टर्मिनेट कर दी जाती हैं. बच्चे, बूढ़े, बीमार, गर्भवती को सामान के साथ लावारिश छोड़ दिया जाता है. मुंबई मंडल, मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा उन पर यह कहकर अहसान भी किया जाता है कि उन्हें उसी टिकट पर लोकल में जाने की अनुमति दी जाती है! एक्सप्रेस का किराया वसूल करके पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कराने को भी रेल प्रशासन उन पर अहसान लादता है. जो खुद अपनी फाइल उठाने के लिए एक मातहत लेकर चलते हों, वे 50-100 किलो सामान के साथ यात्रियों को लोकल ट्रेन, जिसमें यहां सुबह के समय खाली हाथ भी नहीं चढ़ा जा सकता, में यात्रा करने की सलाह देकर अपनी बेशर्मी का परिचय दिया जाता है. रेल प्रशासन को तो उनका अहसानमंद होना चाहिए, जो अपनी सहनशीलता के चलते और अपने पारिवारिक सदस्यों की बलि देकर भी उफ तक नहीं करते, वरना हत्या के षड्यंत्र के गुनहगार रेल प्रशासन को वे न जाने कब का सुधार दिए होते. इसी कड़ी में यह भी उल्लेखनीय है कि जहां 5वीं-छठी लाइन शुरू करते वक्त निर्णय लिया गया था कि संसार के सबसे ज्यादा न्यूट्रल सेक्शन होने तथा कहीं एसी 25000 वोल्ट, तो कहीं डीसी 1500 वोल्ट होने के कारण थोड़ा सा भी भ्रम करोड़ों रु. के इंजन को नष्ट कर सकता है और भारी डिस्लोकेशन हो सकता है. अतः आपातकालीन परिस्थिति में ही चालक को पूर्व सूचना देकर गाड़ियों का मार्ग परिवर्तित किया जाए, अन्यथा सामान्य स्थिति में गाड़ियों का मार्ग परिवर्तित न किया जाए. मगर मुंबई मंडल के भाग्य-विधाता यानि गाड़ी नियंत्रक इन सब उसूलों को कहां मानते हैं. गाड़ी नियंत्रक यहां किसी भगवान से कम नहीं होता. जो लोको पावर कंट्रोलर हैं, वह सब डिफाल्टर हैं और पनिशमेंट पर वहां रेलवे तथा स्टाफ की छाती पर मूंग दल रहे हैं. वे अकर्मण्य बने बैठे रहते हैं.

इस प्रकार मुंबई मंडल में लोको पायलट 'रामभरोसे हिंदू होटल' की तर्ज पर लेट-लतीफ गाड़ियों को चला रहे हैं. जहां अनुभवी चालक रहते हैं, वहां सब संभल जाता है, परंतु जहां रेल प्रशासन द्वारा ढ़केल-ढ़केलकर 8-9 साल में सहायक चालक से सीधे मेल/एक्स. चालक बना दिया जाता है, यानी 4-5 प्रमोशन दे दिए जाते हैं, इअसे लोको पायलटों से रेल परिचालन का बंटाधार हो रहा है. जबकि भारत में पायलेट तो रेडीमेड मिलते हैं, मगर लोको पायलट फिर भी नहीं मिल पाते हैं. यह जानने के बावजूद इस जटिल मंडल में भारत के सर्वाधिक अनुभवहीन चालक यात्री गाडियां चलाते हैं. इस बात की पुष्टि मंडल का सम्बंधित डाटा निकालकर की जा सकती है. कुल 8-9 साल की सर्विस वाला यहां मेल चालक है, जबकि 10-12 साल की सर्विस वाला उसका सहायक चालक है, यह अंधेर तो शायद नरक में भी नहीं होता होगा, जैसा रेलवे में रनिंग स्टाफ की पदोन्नति में किया जा रहा है.

यह कैसी विडंबना है? यह तो सीधे-सीधे करोड़ों यात्रियों के जान-माल और राष्ट्रीय सम्पत्ति के साथ खुला खिलवाड़ है. अब यदि ऐसे में अनुभवहीन चालक से झिग-झेग में गाड़ी चलवाई जाती है, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? कुछ दिन पूर्व यही हुआ. शाम को एक यात्री गाड़ी को जहां ठाणे से 5वीं-6ठी लाइन पर डायवर्ट किया जाता है, वहीं उसको मुलुंड से डायवर्ट किया गया, जबकि उस गाड़ी को सीएसटी जाना था और कोई इमर्जेंसी भी नहीं थी. चालक ने ठाणे-मुलुंड के बीच एसी से डीसी में इंजन के सिस्टम को चेंज किया. पुनः डेढ़ किमी के अंदर उसे मुलुंड से डीसी से एसी में डायवर्ट करने का दोष कंट्रोलर ने किया, जबकि उसे डायवर्ट हुए बिना सीएसटी जाना था. दुर्देव से उसके चालक महोदय को मात्र 9 साल में सहायक चालक से 5 बार पदोन्नत करके रेल प्रशासन द्वारा जबरन मेल चालक बनाया गया था. इस चालक की अनुभवहीनता और कंट्रोलर की गलती या मनमानी के करोड़ों रुपए का लोको जल गया.

अब जहां इसकी जिम्मेदारी कंट्रोलर या जबरन मेल चालक बनाने वाले रेल प्रशासन पर तय की जानी चाहिए थी, वहां इसका सारा दोष कुल 11 साल की सर्विस वाले उक्त अनुभवहीन और जबरन मेल चालक बनाए गए व्यक्ति पर डाल दिया गया. सवाल यह उठता है कि जहां राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान तथा देशवासियों की जान का खतरा हर पल सिर पर मंडरा रहा हो, ऐसे पदों पर इस तरह के जबरन प्रमोशन देना कितना और कहां तक उचित है? यदि फिर भी ये दिए जा रहे हैं, तो उनके द्वारा होने वाले नुकसान की भरपाई और जिम्मेदारी प्रशासन के उस अधिकारी पर व्यक्तिगत तौर पर डाली जाए, जिसने उसे प्रमोशन दिया. गाड़ी संचालन के बारे में कोई भी निर्णय चेंबर में बैठकर करने के बजाय उसकी प्रैक्टिकल बारीकियों को जानकर ही किया जाए, तभी राष्ट्र और राष्ट्र की जनता का भला होगा.

ट्रेन से चोरी गए सामान की कीमत रेलवे को देनी होगी

लखनऊ से जबलपुर लौटते समय 17 साल पहले एसी कोच में जबलपुर की एक महिला प्रोफेसर का पर्स चोरी हो गया था, जिसमें उसके लाखों रुपए के गहने और नकद रुपए थे. पुलिस अब तक चोरी गए उस सामान/गहनों का पता नहीं लगा पाई है. चोरी गए सामान की कीमत अब रेलवे को देनी होगी. हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने रेल यात्रियों को अब न सिर्फ यह सुविधा दिला दी है, बल्कि उसके इस आदेश से रेल यात्रियों को भारी राहत भी मिली है. इसके लिए पीड़ित यात्री को उपभोक्ता फोरम में रेलवे की सेवा में कमी का मामला दायर करना होगा. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अनुसार आरक्षित कोच में अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश रोकना टीटीई की जिम्मेदारी है और अगर वह इसमें नाकाम रहता है, तो यह रेलवे की सेवा में कमी मानी जाएगी.

फरवरी 2014 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ट्रेन से चोरी गए एक महिला प्रोफेसर के सामान की राशि का भुगतान रेलवे को करने का आदेश दिया था. रेलवे ने इस पर दलील दी थी कि यह मामला रेलवे क्लेम्स टिब्यूनल में ही सुना जा सकता है, जबकि यात्री के वकील का कहना था कि क्लेम्स टिब्यूनल में सिर्फ रेलवे में बुक पार्सल/गुड्स के मामलों को ही सुना जाता है. न्यायमूर्ति सी. के. प्रसाद और न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष की पीठ ने 17 साल पुराने इस मामले में रेलवे की दलील को खारिज कर दिया और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले में दखल देने से इंकार कर दिया.

यह अधिकार यात्रियों के लिए जितना सुविधाजनक है, उतना ही रेलवे और पुलिस के लिए अत्यंत मुश्किल भरा साबित होने वाला है. इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि इसकी जानकारी यात्रियों को नहीं है, और न ही इस जानकारी को उन तक पहुंचाने के लिए कोई कारगर कदम उठाए गए हैं. चलती ट्रेन में चोरी होने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराते समय पीड़ित यात्री को इस बारे में पुलिस द्वारा जानकारी नहीं दी जाती है. हालांकि जबलपुर जीआरपी का कहना है कि 1 अप्रैल 2014 के बाद यह आदेश जारी हुआ है और 6 माह बाद यानि सितम्बर से अब तक एक भी मामला नहीं आया है. सर्वोच्च अदालत के उपरोक्त निर्णय के अनुसार चलती ट्रेनों से चोरी गए यात्रियों के सामान की तलाश करने के लिए जीआरपी के पास अब 6 महीने का ही समय होगा. इस दरम्यान यदि पुलिस पीड़ित यात्री का सामान नहीं तलाश पाती है, तो वह उपभोक्ता फोरम में जा सकता है. इसके लिए एफआरआई दर्ज कराते समय पुलिस को पीड़ित यात्री से उपभोक्ता फोरम फार्म भरवाना होगा. ओरिजनल कॉपी पीड़ित यात्री के पास रहेगी, और पुलिस कार्बन कॉपी अपने पास रखेगी. एफआईआर और फार्म ही यात्री का मूल दस्तावेज होगा, जिसके आधार वह उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराएगा.

यह सुविधा सिर्फ स्लीपर या एसी कोच में रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों के लिए है. उपभोक्ता फोरम के जानकार एडवोकेट अरुण कुमार जैन ने बताया कि रिजर्वेशन के दौरान यात्री से 2 रुपए सुरक्षा शुल्क लिया जाता है. इसी के अनुसार यात्री को ट्रेन में स्लीपर कोच दिया जाता है, जिसके बाद यह तय होता है कि उसे ट्रेन में सोने का अधिकार दिया गया है. इस दौरान जो भी घटना होती है, उसका जिम्मेदार रेलवे ही होगा. ट्रेन के स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करते समय यात्री का सामान चोरी होता है, तो शिकायत दर्ज करते समय पुलिस द्वारा उससे उपभोक्ता फोरम का फार्म भरवाया जाना आवश्यक है. यदि 6 माह तक पुलिस उसका सामान नहीं तलाश पाती है, तो वह फार्म की कॉपी ले जाकर उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कर सकता है, जहां पर रेलवे को निश्चित तौर पर पीड़ित यात्री को हर्जाना देना होगा.

व्यंग्य — अतुल मिश्र

तीसरा नेत्र

भारतीय रेल में सफर करते हुए अगर जेब न कटे तो आश्चर्य होता है. कटने पर लोग सोचते हैं कि यह तो होना ही था. टिकट की लाइन से अगर बच भी गए, तो पूरी रेल पड़ी है कि कभी भी जेब साफ करवा दे. रामभरोसे भी इसी डर से अपना वह पर्स, जिसमें कम तनख्वाह और ज्यादा महंगाई के मद्देनजर जितने भी रुपए रखे थे, वह उसने संभालकर अपने बैग में रख लिया था. जेबतराश भी पारखी थे. इसलिए उनका पैरू बैग ही साफ कर गए. अब उन्हें शोर मचाना बाकी था, जो उन्होंने मचाकर अच्छी-खासी भीड़ जमा कर ली. यात्रियों के अलावा कुछ पुलिस वाले, जो यकीनन इसी बात का इंतजार कर रहे थे, रामभरोसे के पास पहुंच गए.

'क्या हुआ?' जब भी कोई वारदात होती है, तो पुलिस वाले सबसे पहले यही सवाल करते हैं, तो जाहिर है कि घटना की भावी तफ्तीश के लिए जरूरी समझते होंगे.

'बैग लेकर भाग गया कोई' रामभरोसे ने रेलवे की पुलिस को देखकर ऐसे जवाब दिया, जैसे उन्हीं में से कोई सिविल ड्रेस पहनकर उनका बैग लेकर भाग गया हो.

'क्या था बैग में?' जेबकतरों के पकड़े जाने पर यह सवाल उतना जरूरी नहीं था, जितना उनके न पकड़े जाने से पहले पुलिस को लगता है. इसी भावना के तहत यह सवाल हुआ.

'दो जोड़ी कपड़े और कुछ रुपए' राम भरोसे के इस जवाब से पुलिसवालों के कान खड़े हो गए.

'कितने रुपए थे?' जेबकतरों के पकड़े जाने पर वास्तव में कितने रुपए दिखाने हैं, इस लिहाज से सवाल हुआ.

'यही कोई हजार-बारह सौ होंगे' चोरी गई रकम को ज्यादा से ज्यादा बताने की बजाय रामभरोसे ने सही बताना जरूरी समझा.

'चलो, हमारे साथ चलो, रिपोर्ट लिखानी होगी.' दोनों पुलिसवाले एक साथ बोले.

'छोड़िये, अब जो हो गया, वो हो गया.' रामभरोसे ने सुन रखा था कि अगर मर भी जाओ, तो अपने मरने की रिपोर्ट लिखाने थाने कभी मत जाना. वरना तुम्हारी लाश के भी कपड़े उतर जाएंगे और फिर नंगे ही पोस्टमार्टम हाउस तक जाना पड़ेगा.

'अजी छोड़िए, जो जिसके भाग्य में था, वह ले गया. अब काहे की रिपोर्ट लिखानी.' रामभरोसे ने अपनी जेब में पड़ी रेजगारी को आशावादी नजरों से टटोलते हुए जवाब दिया.

'ऐसे कैसे नहीं लिखवानी है? रिपोर्ट तो लिखानी जरूरी होती है.' पुलिस वालों की आंखों में रामभरोसे को जो कुछ दिखाई दे रहा था, वह उनके वे कपड़े थे, जो इस समय वे पहने थे, मगर जल्दी ही उतारे जाने थे.

'मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा कुछ भी चोरी नहीं गया.' रामभरोसे ने रेलवे पुलिस से पीछा छुड़ाने की गरज से कहा.

'पुलिस वालों से मजाक?' दोनों पुलिसवाले इतना कहने के बाद रामभरोसे को प्लेटफार्म में मौजूद एक ऐसे कोने में ले गए, जहां पुलिस से मजाक करने की उन गंभीर धाराओं का हवाला देते हुए, जो फिलहाल उन्हें याद नहीं थीं, उनके कपड़े रहने दिए गए, मगर जेब में मौजूद सारी रेजगारी ले ली गई.

'रेल मंत्री' किसी एक प्रदेश विशेष का नहीं, बल्कि पूरे देश का होता है -सुरेश प्रभु

मुंबई में हर दिन कई तरह के आयोजन होते रहते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट जगत से लेकर सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक और मनोरंजन सभी तरह के कार्यक्रम शामिल होते हैं, इन आयोजनों में कॉर्पोरेट जगत से लेकर फिल्मी दुनिया और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल होती हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जो मंच पर मौजूद लोगों के अलावा श्रोताओं के लिए भी यादगार हो पाते हैं. वरना होता यह है कि मंच पर बैठे लोग एक-दूसरे की तारीफों के पुल बाँधते रहते हैं और श्रोता अपने मोबाईल से खेलते रहते हैं. मुंबई के राजस्थान वसति गृह के पूर्व छात्रों के सम्मेलन में ऐसा ही एक अलग नजारा देखने को मिला. इस कार्यक्रम में रेलमंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे. मुंबई के सामाजिक क्षेत्र में अपनी एक खास पहचान बना चुके जाने माने उद्योगपति एवं व्यवसायी रामस्वरुप गाड़िया ने आज से करीब 55 साल पहले मुंबई में चार्टर्ड एकाउंटेंट की पढ़ाई करने आने वाले छात्रों के लिए इस छात्रावास की शुरुआत की थी. यह कार्यक्रम उसी के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था.

रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने अपने खास अंदाज में जिस तरह से इस समारोह को संबोधित किया, वह हर एक श्रोता के लिए एक यादगार अनुभव था. श्री प्रभु ने कहा कि राजस्थान वसति गृह मेरे राजनीतिक जीवन की पहली पाठशाला है. हालांकि मैं इसमें कभी नहीं रहा, मगर यही मेरा खास ठिकाना होता था. तब मैंने 1975 में डब्ल्यूसीएएसए का चुनाव लड़ा था और मात्र 50 रु. डिपाजिट किए थे. इस चुनाव में दो ग्रुप थे. मेरा किसी ग्रुप से कोई लेना-देना नहीं था, मगर मैं चुनाव जीत गया. इसके बाद मैं अपने सभी साथियों को इंडस्ट्रियल टूर पर पुणे लेकर गया, जिसका शुरू-शुरू में तो बहुत विरोध हुआ, लेकिन बाद में सबने इस आईडिया को बहुत पसंद किया था. श्री प्रभु ने कहा कि ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं राजस्थान वसति गृह में नहीं रह सका, लेकिन हर रविवार को यहां का बढ़िया खाना खाने मैं जरूर आता था. उन्होंने कहा कि किसी होस्टल में इतना बढ़िया खाना शायद ही मिले, जितना बढ़िया खाना राजस्थान वसति

चंद्रकांत जोशी*

गृह में मिलता है. श्री प्रभु ने इस होस्टल की कल्पना को साकार करने वाले मंच पर उपस्थित उद्योगपति रामस्वरूप गाड़िया के बारे में कहा कि इस बात की कल्पना करना ही रोमांचक है कि कोई व्यक्ति आज से 55 साल पहले चार्टर्ड एकाउंटेंट बनने आने वाले छात्रों के लिए मुंबई जैसे शहर में होस्टल बनाने की कल्पना करे. उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने ये कल्पना कर उसे साकार करके पूरे समाज के सामने एक अदभुत उदाहरण प्रस्तुत किया है, इनके माता-पिता ने इनका जो नाम रखा है, वह इनके व्यक्तित्व को साकार करता है ङ्क ये वास्तव में 'राम स्वरूप' ही हैं. श्री प्रभु ने कहा कि आज देश भर में 7 हजार चार्टर्ड एकाउंटेंट ऐसे हैं, जो कभी इस संस्थान में छात्र के रूप में रह चुके हैं. सरकार ने तो सीएसआर की योजना अब शुरू की है, मगर श्री गाड़िया ने तो किसी कानून या नियम के बनने से बहुत पहले ही सेवा-भाव के साथ सीएसआर की कल्पना को जन्म दे दिया था. ठहाकों के बीच श्री प्रभु ने कहा कि राजस्थान के जोधपुर की मिट्टी की जांच करवाई जानी चाहिए, क्योंकि अधिकतर चार्टर्ड एकाउंटेंट इसी शहर से बने हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़े रहते हैं.

श्री प्रभु ने स्वच्छ भारत अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, जो स्वच्छता की बात कर रहा है. उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान कोई मामूली सोच नहीं है, अगर हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहता है, तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, हमारे देश के पर्यटन स्थलों का विकास हो सकता है. उन्होंने कहा कि चीन और मोरक्को जैसे देशों में सफाई की बदौलत वहां पर्यटकों की संख्या में वृध्दि हुई है.

कार्यक्रम के बाद श्री प्रभु मंच से उतरकर अपने सभी पुराने साथियों के पास जाकर उनसे मिले. उनके साथ सुरक्षा का कोई तामझाम नहीं था और लोग खुलकर उनसे मिलते रहे. अपने वक्तव्य और व्यवहार-कुशलता से प्रभु ने यह बात साबित कि केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट मंत्री होकर भी जन-सामान्य के बीच सहजता से रहकर लोगों में अपनी व्यापक पहुंच और अपनी व्यापक सोच को स्थापित किया जा सकता है. इससे उन्होंने यह भी संदेश दिया कि 'रेलमंत्री' किसी एक प्रदेश विशेष का नहीं, बल्कि पूरे देश का होता है.

**लेखक 'हिंदी मीडिया' के संपादक हैं*

कुर्क होने से बच गई दिल्ली-ऊना जनशताब्दी एक्सप्रेस

दिल्ली : रेल मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश की ऊना जिला अदालत में गुरुवार, 16 अप्रैल को दो डिमांड ड्राफ्ट जमा करके नई दिल्ली - ऊना जनशताब्दी एक्सप्रेस की कुर्की को रोक कर अपनी फजीहत होने से बचा ली है. अदालत ने एक हफ्ता पहले आदेश दिया था कि अगर रेलवे ने 15 अप्रैल तक 35 लाख 44 हजार रुपए जमा नहीं कराए, तो गुरुवार, 16 अप्रैल को सुबह ऊना स्टेशन पर जनशताब्दी एक्स. को जप्त कर लिया जाए. उल्लेखनीय है कि रेलवे ने 26 लाख 53 हजार और 8 लाख 91 हजार के दो डिमांड ड्राफ्ट कोर्ट में जमा किए. यह राशि दो किसानों - मेलाराम और मदनलाल - को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी.

रेलवे ने अदालत में जमा कराए 26.53 लाख और 8.91 लाख के दो डिमांड ड्राफ्ट

इस दरम्यान अदालत के आदेश के अनुसार कोर्ट का बेलिफ और शिकायतकर्ता स्टेशन पर मौजूद थे. लेकिन रेल अधिकारियों ने गाड़ी चलने से करीब दस मिनट पहले डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी अदालत के कर्मचारी को सौंपकर गाड़ी को जप्त होने से बचा लिया. यह सारा मामला उक्त दोनों किसानों के मुआवजे से जुड़ा है. रेलवे ने ऊना से चुरूड सेक्शन के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिए इन किसानों की जमीन ली थी. हालांकि रेलवे ने किसानों को मुआवजा दिया था. लेकिन मेलाराम और मदनलाल का दावा था कि उन्हें कम पैसे मिले. रेलवे ने जब उनकी बात नहीं मानी, तो सन 2011 में दोनों ने कोर्ट में मामला दाखिल किया था. अदालत ने अपना निर्णय इन दोनों किसानों के पक्ष में दिया है.

अदालत ने रेलवे से मेलाराम को 8.91 लाख और मदनलाल को 26.53 लाख रुपए अतिरिक्त मुआवजा देने के निर्देश दिया था. रेलवे ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है. हालांकि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर स्थगनादेश दिया है, मगर रेलवे को पहले मुआवजे की पूरी राशि अदालत में जमा कराने का निर्देश भी दिया है.

अन्य विभागों के मेडिकली डिकैटेगराइज रेलकर्मियों को वाणिज्य विभाग में पदस्थ किए जाने का विरोध

अन्य विभागों से मेडिकली अनफिट और डिकैटेगराइज रेलकर्मियों को वाणिज्य विभाग और खासतौर पर टिकट चेकिंग ब्रांच में पदस्थ किए जाने के खिलाफ अब वाणिज्य कर्मी अपना खुला विरोध जताने लगे हैं. इसी विषय पर 8 अप्रैल को सभी जोनल और मंडल मुख्यालयों में जीएम एवं डीआरएम को टिकट चेकिंग स्टाफ के लोगों ने एकजुट होकर ज्ञापन दिया. पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल मुख्यालय में डीआरएम को ज्ञापन सौंपने के लिए मंडल मुख्य टिकट निरीक्षक श्री शर्मा के साथ सीटीआई बंशी श्रीवास्तव और बी. एस. परिहार सहित टिकट चेकिंग स्टाफ के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीआरएम/भोपाल आलोक कुमार को एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा गया है कि रेल प्रशासन द्वारा अन्य विभागों से मेडिकली अनफिट और डिकैटेगराइज रेलकर्मियों को वाणिज्य विभाग में पदस्थ किए जाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वह कतई उचित नहीं है. इससे टिकट जांच सहित सभी वाणिज्य कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है. ज्ञापन में इस प्रस्ताव को अविलंब वापस लिए जाने की मांग की गई है.

साहित्यकर्मी रेल अधिकारी प्रेमपाल शर्मा सेवानिवृत्त

रेलवे बोर्ड में लंबी रेल सेवा के बावजूद एक रेल अधिकारी के रूप में कम, साहित्यकार के रूप में अपनी बेहतर पहचान बनाने वाले जाने-माने लेखक, कथाकार प्रेमपाल शर्मा ने 31 मार्च को रेल मंत्रालय को अलविदा कह दिया. हालांकि वे 31 अक्टूबर 2016 को साठ वर्ष के होने वाले थे और उनकी साहित्यिक बिरादरी तभी उन्हें साठ का मानेगी तथा तभी वह उनका साठा भी मनाएगी, मगर आज से साठ साल पहले जैसे अपने बड़े-बुजुर्गवार स्कूल में नाम लिखाने की जल्दी में बच्चों की उम्र एकाध साल ज्यादा लिखा दिया करते थे, श्री शर्मा के साथ भी यही हुआ था. तथापि 31 मार्च को रेल मंत्रालय से विदा होते समय उनके चेहरे अथवा मन में इस बात का कोई मलाल नहीं दिखाई दिया, बल्कि एक तरह से वह इस बात के लिए बहुत सुकून महसूस कर रहे थे कि एक साल सात महीने पहले सरकारी सेवा से मुक्त होकर अब शायद और ज्यादा बेहतर साहित्यिक सृजन कर सकेंगे.

डीपीओ मुंबई सेंट्रल अरुण सोनावने को जीएम अवार्ड

मुंबई सेंट्रल मंडल, पश्चिम रेलवे के मंडल कार्मिक अधिकारी (डीपीओ) श्री अरुण ए. सोनावने को सराहनीय कार्य के लिए महाप्रबंधक श्री एस. के. सूद द्वारा महाप्रबंधक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. श्री सोनावने ने 'अपने कर्मचारी को जानें' (केवाईई) कार्यक्रम के अंतर्गत मंडल के सभी रेलकर्मियों को उनकी सेवा-पंजिका अद्यतन अपडेट) कर दी है. उनके द्वारा किए गए लगातार प्रयास के फलस्वरूप रेलवे सेकेंडरी स्कूल, वलसाड की सीबीएसई बोर्ड से सम्बद्धता हासिल हो पाई है. श्री सोनावने लगातार लार्सजेस, सीजीए एवं सत्यापन प्रकरणों की निगरानी करते हैं और समय पर उनका निपटारा भी करवाते हैं. उनके रेलवे के विविध आवासों के औचक निरीक्षण के चलते उनमें असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोका जा सका है. उन्होंने अपने विशेष प्रयासों से एक साल में करी 1300 आरटीआई मामलों का निपटारा किया और किसी भी मामले में सीआईसी की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं मिली. उनकी व्यवहार कुशलता से मंडल में विभिन्न श्रमिक संगठनों और कर्मचारियों के साथ औद्योगिक संबंध भी सामान्य रहे हैं. महाप्रबंधक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर श्री सोनावने को सभी सहयोगी अधिकारियों और कर्मचारियों ने बधाई दी है.

पू.र.के कर्मचारियों के लिए बना नया सामुदायिक भवन

गोरखपुर : पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए गोरखपुर स्थित डेरी रेलवे कॉलोनी में नए सामुदायिक सभागृह का निर्माण किया गया है. मंगलवार, 10 अप्रैल को इस नवनिर्मित सामुदायिक भवन का औपचारिक उदघाटन पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्रा ने किया. इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य विद्युत् अभियंता (सीईई) राजेंद्र निबारिया सहित सभी विभाग प्रमुखों सहित बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे. इसके अलावा 60वें रेल सप्ताह के अवसर पर महाप्रबंधक राजीव मिश्रा ने पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक फोटो प्रदर्शनी का भी उदघाटन किया. इस मौके पर उनके साथ पूर्वोत्तर रेलवे के सभी विभाग प्रमुखों ने भी फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया.

60वें रेल सप्ताह के अवसर पर पूर्व रेलवे ने पूर्व क्षेत्र में रेलवे के 160 वर्ष का जश्न मनाया

(बाएं) हावड़ा मंडल को वर्ष 2014-15 के दौरान बेहतर एवं सराहनीय कार्य-निष्पादन के लिए समग्र दक्षता शील्ड और (दाएं) सियालदह मंडल को दक्षता रनर-अप कप बैज एवं साफ-सफाई शील्ड प्रदान करते हुए पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक श्री आर. के. गुप्ता.

कोलकाता : भारत के पूर्व क्षेत्र में रेलवे के 160 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूर्व रेलवे ने 15 अप्रैल को डॉ. बी. सी. रॉय ऑडिटोरियम, सियालदह में अपना 60वां रेल सप्ताह समारोह मनाया. महाप्रबंधक ने 88 चुनिंदा रेलकर्मियों और 22 अधिकारियों को उनकी समर्पित एवं सराहनीय सेवाओं के लिए 32 दक्षता शील्ड, नकद पुरस्कार, प्रमाण-पत्र और बैज प्रदान सहित 14 समूह पुरस्कार प्रदान किए. इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक श्री बी. के. पटेल और सभी विभाग प्रमुखों सहित पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष श्रीमती वीणा गुप्ता भी उपस्थित थीं.

इस मौके पर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक श्री आर. के. गुप्ता ने हावड़ा मंडल को वर्ष 2014-15 के दौरान बेहतर और सराहनीय कार्य-निष्पादन के लिए समग्र दक्षता शील्ड और सियालदह मंडल को दक्षता रनर-अप कप बैज प्रदान किया. इसके साथ ही साफ-सफाई शील्ड भी सियालदह मंडल को प्राप्त हुई है. इस अवसर पर अपने संबोधन में महाप्रबंधक श्री गुप्ता ने कहा कि पूर्व रेलवे ने गाड़ियों के समपालन, संरक्षा, सुरक्षा, साफ-सफाई और कार्य-निष्पादन के क्षेत्र में बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने वर्ष 2014-15 के दौरान 67.247 मिलियन टन माल ढुलाई के लक्ष्य को हासिल करने और 115.60 करोड़ यात्रियों के परिवहन में पूर्व रेलवे के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के योगदान की सराहना भी की.

द.म.रे. को मिलीं सराहनीय कार्य-निष्पादन के लिए चार दक्षता शील्ड्स

सिकंदराबाद : दक्षिण मध्य रेलवे को वर्ष 2014-15 के दौरान उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए सिविल इंजीनियरिंग, स्टोर्स, बिक्री प्रबंधन और रनिंग रूम (विजयवाड़ा) वर्ग की राष्ट्रीय स्तर की चार दक्षता शील्ड प्राप्त हुई हैं. यह शील्ड्स द.म.रे. के महाप्रबंधक श्री पी. के. श्रीवास्तव को 13 अप्रैल को गुवाहाटी में आयोजित 60वें राष्ट्रीय रेल पुरस्कार वितरण समारोह में रेलमंत्री श्री सुरेश प्रभु ने प्रदान कीं.

मंडल रेल प्रबंधक, जयपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे का 24 मार्च को पदभार ग्रहण करने के बाद मंडल अधिकारियों के साथ नई मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती अंजलि गोयल. उन्होंने निवर्तमान मंडल रेल प्रबंधक वीरेंद्र कुमार से यह पदभार लिया है. डीआरएम/जयपुर बनकर आने से पहले श्रीमती अंजलि गोयल सलाहकार के पद पर योजना आयोग, दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर थीं. श्रीमती गोयल के डीआरएम बनकर आने से जयपुर मंडल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है.

रेलवे की बिजली से रोशन हो रहा पूरा शहर

जमालपुर (मुंगेर) : रेल प्रशासन के लाख चौकसी के बावजूद जमालपुर शहर का दो तिहाई से ज्यादा हिस्सा रेलवे की बिजली से रोशन हो रहा है. बताते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि इस तमाम गोरखधंधे के बारे में रेल प्रशासन कुछ मालूम नहीं है. जाहिर है कि इसमें रेलवे के बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों सहित आरपीएफ और शहर के बिजली माफिया की पूरी मिलीभगत है. उसकी इस मिलीभगत के बिना इतने बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का यह अवैध कारोबार चल ही नहीं सकता है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार जमालपुर शहर के सदर बाजार, खलासी मोहल्ला, जनता मोड़, बड़ी केशोपुर, ईदगाह रोड, धरहरा रोड, वलीपुर, रामपुर, दौलतपुर, दरियापुर, गायत्री नगर आदि में रेलवे की बिजली धड़ल्ले से जलाई जा रही है. रेलवे की बिजली इस्तेमाल करने के लिए बिजली माफिया को 300 से 600 रुपया प्रतिमाह देना पड़ता है. बताया जाता है कि शहर में आधा दर्जन से ज्यादा बिजली माफिया द्वारा 20 से 25 हजार की वसूली की जारी है. इस वसूली में रेलवे के कुछ बिजली कर्मचारियों और आरपीएफ की भी हिस्सेदारी होती है. हालांकि रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर बिजली चोरी के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया जाता है, पर यह सिर्फ दिखावा होता है. शहर में तेजी से रेलवे की बिजली की चोरी होने से रेलवे को प्रतिमाह करोड़ों रुपए की क्षति हो रही है.

इलाहाबाद जं. पर जनसम्पर्क विभाग का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम

इलाहाबाद : रेल सप्ताह के दौरान 16 अप्रैल को उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री वी. के. त्रिपाठी की उपस्थिति में इलाहाबाद जंक्शन पर जनसम्पर्क विभाग द्वारा 'बिग एफएम' के सौजन्य से एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में रेल यात्रियों को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर रेलवे से जुड़ी जानकारियों वाले कई रोचक प्रश्न पूछे गए. इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के दौरान सही उत्तर देने वाले रेल यात्रियों को मंडल रेल प्रबंधक श्री त्रिपाठी ने पुरस्कृत भी किया.

अपनी स्थापना के 12 वर्षों के दौरान द.प.रे. ने बेहतर प्रदर्शन किया है -पी.के.सक्सेना

हुबली : दक्षिण पश्चिम रेलवे ने अपना 60वां रेल सप्ताह समारोह शुक्रवार, 17 अप्रैल को चालुक्य रेलवे इंस्टिट्यूट, गदग रोड, हुबली में मनाया. समारोह का उदघाटन दीप प्रज्वलित करके द.प.रे. के महाप्रबंधक और समारोह के मुख्य अतिथि पी. के. सक्सेना ने किया. इस अवसर पर द.प.रे. महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष श्रीमती नीलिमा सक्सेना, मुख्य कार्मिक अधिकारी के. हरेकृष्णन, मुख्य यांत्रिक अभियंता वशिष्ठ जौहरी, प्रमुख मुख्य अभियंता संजीव रॉय, मुख्य परिचालन प्रबंधक पी. गणेश्वर राव, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक विशाल अग्रवाल सहित डीआरएम/हुबली संजीव मित्तल, डीआरएम/मैसूर राजकुमार लाल, डीआरएम/बंगलौर संजीव अग्रवाल और सभी अन्य विभाग प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारीगण उपस्थित थे.

इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री सक्सेना ने कहा कि वर्ष 2014-15 में द.प.रे. ने समग्र कार्य-निष्पादन के के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है. महाप्रबंधक श्री सक्सेना ने कहा कि अपनी स्थापना के इन 12 वर्षों में द.प.रे. ने आय एवं वित्तीय स्तर पर बेहतर कार्य कुशलता का प्रदर्शन किया है. उन्होंने बताया कि मार्च 2015 में द.प.रे. की आय 17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1820 करोड़ रुपए रही है. वित्तवर्ष 2014-15 में द.प.रे. ने कुल 37.50 मिलियन टन माल का लदान किया है. जो कि गत वर्ष 2013-14 की तुलना में 5 प्रतिशत ज्यादा है. माल भाड़ा आय 13 प्रतिशत बढ़कर कुल 3378 करोड़ रुपए रही है. उन्होंने कहा कि परिचालन औसत में भी 10 प्रतिशत का सुधार हुआ है. श्री सक्सेना ने इस सराहनीय कार्य-निष्पादन और परिचालन औसत में उल्लेखनीय सुधार का श्रेय द.प.रे. के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया.

दक्षिण पश्चिम रेलवे ने मनाया 60वां रेल सप्ताह समारोह

इस मौके पर श्री सक्सेना ने द.प.रे. मुख्यालय सहित तीनों मंडलों, कारखानों एवं डीजल शेडों के 16 अधिकारियों सहित कुल 123 कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए पदक, प्रमाण-पत्र और नकद पुरस्कार सहित कुल 20 महाप्रबंधक दक्षता शील्ड्स प्रदान किन. बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए समग्र कार्यकुशलता शील्ड हुबली मंडल को मिली, जिसे डीआरएम/हुबली संजीव मित्तल और उनके सभी ब्रांच अधिकारियों ने मिलकर महाप्रबंधक के हाथों ग्रहण किया. इसके अलावा मेडिकल, कार्मिक, संकेत एवं दूरसंचार, अंतरमंडलीय राजभाषा रोलिंग शील्ड भी हुबली मंडल को मिलीं हैं. लेखा दक्षता शील्ड और परिचालन दक्षता शील्ड संयुक्त रूप से हुबली एवं मैसूर मंडल को दी गई हैं. जबकि वाणिज्य, यांत्रिक और सुरक्षा दक्षता शील्ड बंगलौर मंडल को प्राप्त हुई हैं. इसके साथ ही विद्युत् दक्षता शील्ड बंगलौर एवं मैसूर मंडल को संयुक्त रूप से दी गई है. इंजीनियरिंग दक्षता शील्ड और अंतरमंडलीय संरक्षा दक्षता शील्ड मैसूर मंडल को मिली हैं.

जोनल महाप्रबंधकों को ही प्राथमिकता...

पेज 1 से आगे... अधिकारियों की परफार्मेंस रिव्यू की भी सिफारिश की है. उन्होंने यह रिपोर्ट रेलमंत्री सुरेश प्रभु को सौंपी है. माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के कुछ पहलुओं को जल्द ही लागू किया जा सकता है.

सुरेश प्रभु ने रेलमंत्री का पदभार संभालने के बाद रेलवे बोर्ड में कार्य कर चुके श्रीधरन को भारतीय रेल की प्रशासनिक और आर्थिक स्थिति सुधारने संबंधी सिफारिशें देने का काम सौंपा था. श्रीधरन ने रेलमंत्री को सौंपी गई अपनी फाइनल रिपोर्ट में कहा है कि ट्रेनों में कैटरिंग का काम रेलवे को अपने पास रखने के बजाय इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन को सौंप देना चाहिए.

उन्होंने रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह की है कि रेलवे बोर्ड के कार्यों और अधिकारों को सीमित किया जाए. ज्ञातव्य है कि रेलवे बोर्ड द्वारा फिलहाल पॉलिसी बनाने से लेकर टेंडर मंजूर करने तक के काम किए जाते हैं, जिससे रेलवे का केंद्रीयकरण हो गया है. श्रीधरन का मानना है कि अधिकारों के विकेंद्रीकरण के लिए जरूरी है कि रेलवे बोर्ड को सिर्फ पॉलिसी बनाने तक सीमित रखा जाए. उन्होंने अपनी सिफारिश में यह भी कहा है कि आरडीएसओ से भी खरीदारी और मंजूरी संबंधी कामकाज वापस ले लिया जाना चाहिए.

श्रीधरन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जोनल महाप्रबंधकों को सभी तरह के टेंडर मंगाने से लेकर उन्हें फाइनल करने का अधिकार दिया जाना चाहिए. यही नहीं, जोनल महाप्रबंधकों को यह अधिकार भी होना चाहिए कि वे अपने जोन की परियोजनाओं को मिले फंड का उपयोग दूसरी और ज्यादा जरूरी रेल परियोजनाओं के लिए कर सकें. श्रीधरन का मानना है कि जोनल महाप्रबंधकों को ही रेल परियोजनाओं की प्राथमिकताएं तय करने का अधिकार होना चाहिए. इसके साथ ही किस अधिकारी या कर्मचारी को किस काम में और कहां पदस्थ किया जाए, यह भी तय करने का सम्पूर्ण अधिकार जोनल महाप्रबंधकों को ही होना चाहिए.

श्रीधरन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि निर्माण संबंधी कामकाज और रख-रखाव के ठेकों के लिए बहुत पहले तय किए गए नियम बेहद पुराने और काफी उलझे हुए हैं, जिससे टेंडर्स का निर्धारित समय में आवंटन नहीं हो पाता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि विज्ञापन से लेकर कंस्ट्रक्शन के सामान्य नियमों को बदले हुए समय और जरूरत के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए. रेलवे में चल रही लेखा एवं वित्त विभाग की मनमानी को ध्यान में रखते हुए समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि जोनल स्तर पर महाप्रबंधकों को ही यह अधिकार होना चाहिए कि पैसा कहां और कैसे खर्च होगा. इसके लिए जानल महाप्रबंधकों को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह वित्त एवं लेखा विभाग की आपत्तियों को नजरंदाज कर सकें.

रेलवे बोर्ड में बड़े पैमाने पर संभावित...

पेज 1 से आगे... तैनात रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के कार्यालय सहायक से लेकर निदेशक स्तर तक के सभी अधिकारियों का तबादला किया जाना चाहिए. इस सिफारिश को मंजूर करते हुए रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने की स्वीकृति दे दी थी, जिसके बाद से उन अधिकारियों और कर्मचारियों में भारी हड़कम्प मचा हुआ है, जो काफी लंबे समय से मलाईदार पदों और मनमाफिक निदेशालयों में पदस्थ रहे हैं.

रेलवे बोर्ड के हमारे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इस रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आरबीएसएस) के निदेशक से लेकर सहायक स्तर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों के विभागों एवं निदेशालयों में फेरबदल किया जाना है. पहले चरण में दस वर्ष से अधिक समय तक एक जगह तैनात रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का एक अप्रैल तक जबकि पांच वर्ष से एक ही पद पर पदस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों का 30 अप्रैल तक फेरबदल किया जाना है.

सूत्रों का कहना है कि इस फेरबदल को टालने के लिए रेलवे बोर्ड के सम्बंधित अधिकारियों द्वारा रेलमंत्री के पास यह तर्क दिया गया कि यदि एक झटके में यह बदलाव कर दिए गए, तो कामकाज प्रभावित हो सकता है. इस तर्क के कारण बाद में यह रास्ता निकाला गया कि चरणबद्ध तरीके से फेरबदल किया जाए, ताकि कामकाज प्रभावित न हो. चूंकि पहली अप्रैल से इस आदेश को अमल में लाना था, इसलिए एक अप्रैल तक करीब 25 कार्यालय सहायकों और 15 सेक्शन अफसरों के तबादले रेलवे बोर्ड में ही एक जगह से दूसरी जगह कर दिए गए हैं. अभी ढेर सारे और अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया जाना है.

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 'रेलवे समाचार' पिछले 10-12 साल से लगातार इस मामले को उठता रहा है और बार-बार इस संबंध में खबरें प्रकाशित करता रहा है कि रेलवे बोर्ड में लम्बे समय से एक ही पद और एक ही निदेशालय में तैनात आरबीएसएस के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी रेलवे बोर्ड की पीरियोडिकल पालिसी लागू की जाए और इसके साथ ही उनका तबादला भी रेलवे बोर्ड से बाहर जोनल रेलों में किया जाना चाहिए. 'रेलवे समाचार' की इसी बात की पुष्टि अब डॉ. देबरॉय समिति ने भी की है. रेल मंत्रालय में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण आरबीएसएस के कर्मचारियों और अधिकारियों का लम्बे-लम्बे समय तक एक ही पद और एक ही निदेशालय में बने रहना है. रेलमंत्री सुरेश प्रभु को चाहिए कि काम प्रभावित होने जैसे बोर्ड अधिकारियों के बहानो को दरकिनार करके समिति की सिफारिशों को एकमुश्त लागू करें.

भारतीय रेलवे के करीब 80 हजार तकनीकी सुपरवाइजर्स की वेतन संबंधी मांगों को सातवें वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करते हुए ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के महामंत्री कॉम. शिवगोपाल मिश्रा. उनके साथ कॉम. मुकेश माथुर और कई अन्य वरिष्ठ यूनियन पदाधिकारी भी थे.

द.प.रे. के एसीएम राजकुमार को जीएम अवार्ड

हुबली : दक्षिण पश्चिम रेलवे के सहायक वाणिज्य प्रबंधक श्री राजकुमार नागराजन को उनकी बेहतर और सराहनीय सेवाओं के लिए महाप्रबंधक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. श्री राजकुमार ने यात्री विपणन, खानपान, टिकट जांच और स्थापना आदि विषयों में कड़ी मेहनत करके बहुत व्यापक सुधार किए हैं. बीते वर्ष 2014-15 में उन्होंने यात्री आरक्षण व्यवस्था में सुधार करके रेलवे के लिए कुल 151.78 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया. इसके साथ ही उन्होंने 13 गाड़ियों में 15 अतिरिक्त स्थाई कोच जोड़कर 13.36 करोड़ रुपए की अन्य आय हासिल की. 17 अप्रैल को चालुक्य इंस्टिट्यूट, हुबली में आयोजित रेल सप्ताह समारोह में दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री पी. के. सक्सेना के हाथों पदक, नकद राशि और प्रमाण पत्र स्वीकार करते हुए एसीएम राजुमार नागराजन.

एनआईडी, अहमदाबाद में 'रेलवे डिजाइन सेंटर' की स्थापना

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी) अहमदाबाद में 'रेलवे डिजाइन सेंटर' की स्थापना हेतु रेल मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच 10 अप्रैल को रेल भवन, नई दिल्ली में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए. इस अवसर पर उपस्थित रेलमंत्री सुरेश प्रभु और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन के साथ वित्तायुक्त/रेलवेज श्रीमती राजलक्ष्मी रविकुमार एवं अन्य अधिकारी.

यशवंत चौधरी को रेलमंत्री अवार्ड

कोटा मंडल, पश्चिम मध्य रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री यशवंत कुमार चौधरी को उत्कृष्ट एवं सराहनीय रेल सेवाओं के लिए 13 अप्रैल को गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय रेल पुरस्कार वितरण समारोह में रेलमंत्री श्री सुरेश प्रभु द्वारा रेलमंत्री अवार्ड ने सम्मानित किया गया है. रेलमंत्री अवार्ड लेकर कोटा पहुंचने पर कोटा मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सड़क पर जुलूस निकालकर श्री चौधरी का भव्य स्वागत किया. इस मौके पर मंडल के सभी सहयोगी अधिकैयों और वाणिज्य कर्मचारियों ने श्री चौधरी को बधाई दी है.

रेलमंत्री की सख्ती से आना शुरू हुआ गाड़ियों के सही समयपालन...

पेज 1 से आगे... की इस सख्ती के बाद गाड़ियों के आवागमन की काफी हद तक सही फीडिंग हो रही है, जिसके चलते कई जोनों में गाड़ियों के समय पालन का आंकड़ा 99% से गिरकर सीधे 80% पर आ गया है. इस संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में यह आंकड़ा 100% समय पालन से गिरकर अब 85% पर आ गया है. रेल प्रशासन ने इसके लिए काम के प्रति भारी लापरवाही करने वाले मंडल के दो डिप्टी कंट्रोलर को निलंबित कर दिया है. मंडल रेल प्रबंधक और उनके सभी ब्रांच अधिकारी मिलकर अब फिर शत-प्रतिशत समयपालन को सुनिश्चित करने में जुट गए हैं. यह शायद पहला अवसर होगा जब इस संदर्भ में मेंबर ट्रैफिक के सख्त आदेश के तहत किसी मंडल में कोई निलंबन हुआ है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त दोनों डिप्टी कंट्रोलर्स द्वारा रेलवे के सिस्टम में देरी से चल रही कई गाड़ियों को सही समय पर चलने या मात्र 10-15 मिनट लेट दिखाया जा रहा था. जबकि असलियत में ये गाड़ियां घंटों लेट होती थीं. लाइन ट्रेन जैसे सिस्टम ने अब रेलवे को यह सुविधा प्रदान कर दी है कि उसमें गलत जानकारी दर्ज करने पर वह उसे स्वीकार ही नहीं करता है. इसके अलावा अब कोई भी यात्री अपनी गाड़ी के देरी से या निर्धारित समय से चलने और उसकी लोकेशन की ऑनलाइन जानकारी बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है. अत्याधुनिक तकनीक ने रेलवे और इसके कर्णधारों को मजबूर कर दिया है कि वे अब पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करें, क्योंकि उनके प्रत्येक कामकाज पर अब हर किसी की लगातार नजर बनी हुई है. बताते हैं कि जोधपुर स्टेशन पर घंटों से गाड़ी का इंतजार कर रहे यात्रियों को जब ऑनलाइन सिस्टम से पता चला कि कई घंटे देरी से पहुंची गाड़ी को सही समय पर पहुंचना दर्शाया गया है, तो यात्रियों ने इसकी शिकायत की. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसी शिकायतों की लंबी सूची पीएमओ ने रेल मंत्रालय को सौंपी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे के नए सिस्टम के तहत गाड़ी के 15 मिनट तक देरी से चलने को सामान्य माना जाएगा, लेकिन इससे अधिक देरी होने पर परिचालन से जुड़े प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी. देरी के कारणों की समीक्षा की जाएगी और यदि सिस्टम की परेशानी है तो उसमें सुधार किया जाएगा.

इलाहाबाद मंडल को मिली सर्वोत्तम मंडल की समग्र कार्य-निष्पादन शील्ड

इलाहाबाद : उत्तर मध्य रेलवे में 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मनाए गए रेल सप्ताह समारोह का मुख्य पुरस्काकर वितरण समारोह 15 अप्रैल को प्रधान कार्यालय, सूबेदारगंज, इलाहाबाद में उ. म. रे. के महाप्रबंधक महेश मंगल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया. उल्लेखनीय है कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे की पहली शुरुआत के उपलक्ष्य में सम्पूर्ण भारतीय रेल में वर्ष 1956 से प्रति वर्ष रेल सप्ताह समारोह का आयोजन किया जाता है. इस अवसर पर अपने सम्बोधन में महाप्रबंधक महेश मंगल ने रेलमंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में गुवाहाटी में 13 अप्रैल को आयोजित भारतीय रेल के राष्ट्रीय रेल सप्ताह समारोह में वर्ष 2014-15 के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए उ.म.रे. को यांत्रिक इंजीनियरिंग शील्ड प्रदान किए जाने पर उ.म.रे. के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी.

उ.म.रे. के जनसम्पर्क विभाग द्वारा बनाई गई डाक्यूमेंट्री 'विकास गाथा - उत्तर मध्य रेलवे की' का विमोचन करते हुए उ.म.रे. के महाप्रबंधक श्री महेश मंगल और उ.म.रे. के सभी विभाग प्रमुख. उनके साथ हैं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बिजय कुमार (एकदम बाएं).

■ उ. म. रे. में पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया 60वां रेल सप्ताह समारोह

महाप्रबंधक ने उ.म.रे. के 5 अधिकारियों एवं कर्मचारियों राज कुमार - पोर्टर, आर. एन. त्रिपाठी - लोको पायलट, सुधीर कुमार श्रीवास्तव - जूनियर इंजीनियर, पी. एस. बिष्ट - वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, इलाहाबाद मंडल, भूरेलाल, उप मुख्य इंजीनियर को भी अनुकरणीय कार्य करने के लिए रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किए जाने के साथ ही अजय कुमार मिश्र, सहायक सामग्री प्रबंधक को स्क्रैप डिस्पोजल में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए और मुख्य सतर्कता निरीक्षक बी. के. खरे को निबंध लेखन में पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई दी. रेल सप्ताह के दौरान उ.म.रे. के विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर फोटो रेल प्रदर्शनियां लगाई गईं.

महाप्रबंधक ने उ.म.रे. की वर्ष 2014-15 की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि उ.म.रे. ट्रंक रूटों के माध्यम से देश के उत्तरी भाग को पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी भागों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान उ.म.रे. की प्रारंभिक आय में लगभग 12.15त्न तथा परिचालनिक आय में लगभग 11.44त्न की वृद्धि दर्ज हुई है. इस वर्ष झांसी में प्रतिवर्ष 250 सवारी डिब्बों के पुनर्निर्माण की क्षमता वाले नए कोच मिड लाइफ रिहैबीलिटेशन कारखाने का शुभारंभ कर उ.म.रे. ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान में उत्तर मध्य रेलवे अपना सक्रिय योगदान दे रही है. इस दिशा में उल्लेखनीय परिवर्तन लाने के लिए सघन स्वच्छता और व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया गया है. समाचार पत्रों और व्यक्तिगत संपर्कों जैसे परंपरागत माध्यमों के अतिरिक्त डिजिटल सिनेमा, एसएमएस, टेलीविजन, रेडियो जैसे विभिन्न आधुनिक संचार माध्यमों से इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. यात्री सुविधाओं की चर्चा करते हुए महाप्रबंधक ने बताया कि इलाहाबाद मंडल के छिंवकी स्टेशन को सेटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है. इस स्टेशन के नए भवन का निर्माण कर इसी वर्ष उसे चालू किया गया है. यात्रियों की सुविधा के लिए मथुरा में दो दरवाजे तथा ईदगाह में एक और प्रवेश द्वार खोला गया है. विश्रामालयों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है.

इलाहाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक वी. के. त्रिपाठी को सर्वोत्तम मंडल की समग्र कार्य-निष्पादन दक्षता शील्ड प्रदान करते हुए उ.म.रे. के महाप्रबंधक श्री महेश मंगल.

झांसी मंडल को जनसंपर्क विभाग की समग्र दक्षता शील्ड प्रदान करते हुए उ.म.रे. के महाप्रबंधक श्री महेश मंगल और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री बिजय कुमार.

महाप्रबंधक ने कर्मचारी कल्याण से जुड़ी गतिविधियों के विषय में बताते हुए कहा कि रनिंग कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आगरा कैंट में एक नया दो मंजिला रनिंग रूम चालू कर दिया गया है. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिए 'अर्पण' योजना शुरू की गई है. कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए केंद्रीय चिकित्सालय, इलाहाबाद में कंप्यूटरीकृत रेडियोग्राफी सिस्टम और कैंटीन की सुविधा प्रारंभ की गई. कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए आगरा कैंट में कैरिज एवं वैगन कर्मचारियों के लिए एक बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र का आरंभ किया गया तथा हाल ही में आगरा और मथुरा में नए अधिकारी विश्रामगृह बनाए गए हैं.

कारखानों और अन्य इकाईयों के कर्मचारियों की संवर्ग पुनर्संरचना कर ली गई है. इस संवर्ग पुनर्संरचना के अंतर्गत कुल 11050 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है, जिसमें ट्रैकमैन संवर्ग के 5043 और अन्य संवर्गों के 6007 कर्मचारी शामिल हैं. इसके अतिरिक्त वर्ष 2014 में 2842 कर्मचारियों को चयन, उपयुक्तता एवं व्यावसायिक परीक्षण के तहत पदोन्नत किया गया है. सांस्कृतिक कोटे के तहत 2 अभ्यर्थी, खेलकूद कोटे के अंतर्गत 35 अभ्यर्थियों और स्काउट एवं गाइड कोटे के अधीन 8 अभ्यर्थियों का पैनल जारी किया गया. भूतपूर्व सैनिकों के लिए 535 रिक्तियों सहित 2691 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत लगभग 15 लाख आवेदन पत्र प्राप्तस हुए थे. इसके लिए नवम्बर, 2014 में लिखित परीक्षा 5 चरणों में सम्पन्न हुई थी, जिसका परिणाम 31 जनवरी 2015 को घोषित किया गया था और सफल अभ्यआर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 से 14 मार्च, 2015 को की गई है.

उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 के दौरान समापन भुगतान संबंधी 3805 मामलों का निस्तारण किया गया तथा अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति संबंधी 562 मामलों को अंतिम रूप दिया गया. 16 जून 2014 को सम्पन्न पेंशन अदालत में 215 तथा 15 दिसंबर 2014 को सम्पन्न? पेंशन अदालत में 450 मामलों का निस्तारण किया गया. राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इलाहाबाद द्वारा उ.म.रे. प्रधान कार्यालय को वर्ष 2014-15 के लिए नगर राजभाषा का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया. इस अवसर पर महाप्रबंधक महेश मंगल ने जनसम्पर्क विभाग द्वारा बनाई गई डाक्यूमेंट्री 'विकास गाथा - उत्तर मध्य रेलवे की' का विमोचन किया. वर्ष 2014-15 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उ.म.रे. के विभिन्न मंडलों तथा इकाईयों को 32 शील्ड तथा 25 अधिकारियों और 138 कर्मचारियों को व्यक्तिगत प्रशस्ति पत्र तथा नगद पुरस्कार प्रदान किए गए. इलाहाबाद मंडल को सर्वोत्तम मंडल की समग्र कार्य-निष्पादन दक्षता शील्ड एवं वाणिज्य विभाग शील्ड सहित कुल 14, आगरा मंडल को समग्र सुधार शील्ड सहित 5 तथा झांसी मंडल को जनसम्पर्क विभाग की दक्षता शील्ड सहित 5 अन्य शील्ड प्रदान की गईं. इसके अतिरिक्त झांसी और सिथौली कारखाना सहित झांसी डिपो को एक-एक शील्ड प्राप्त हुई है. इस अवसर पर उ.म.रे. के सभी विभाग प्रमुखों सहित तीनों मंडलों एवं सभी इकाईयों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे.

महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमांत श्री आर. एस. विर्दी से जोनल सुरक्षा दक्षता शील्ड ग्रहण करते हुए तिनसुकिया मंडल के मंडल रेल प्रबंधक एवं सहायक सुरक्षा अधिकारी मो. अहसान. सुरक्षा शील्ड के साथ खुशी मानते तिनसुकिया मंडल, रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य. महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमांत श्री आर. एस. विर्दी से महाप्रबंधक अवार्ड लेते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे/निर्माण के मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री अखिलेश चंद्रा. समारोह में उपस्थित रेलवे सुरक्षा बल सदस्यों ने एक विशेष खामी की तरफ ध्यान आकर्षित किया, वह यह कि श्री चंद्रा ने ऐसे विशेष अवसरों पर आरपीएफ वर्दी का अनिवार्य हिस्सा 'क्रॉस बेल्ट' नहीं पहना था, जो कि जीएम प्रोटोकॉल का उल्लंघन है.

आजीवन सदस्यता 3000 रु.,
संरक्षक सदस्यता 5000 रु.,
कृपया चेक/डीडी 'सोहम पब्लिकेशन' के नाम निम्नलिखित संपादकीय कार्यालय के पते पर भेजें.

परिपूर्ण रेलवे समाचार
रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

संपादकीय कार्यालय
रूम नं. 105, डॉक्टर हाउस,
पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास,
कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे. (महाराष्ट्र)
मोबाइल नं. : 9869256875

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक सुरेश त्रिपाठी द्वारा सोहम पब्लिकेशन, 105, डॉक्टर हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे. (महाराष्ट्र) से मुद्रित एवं 105, डॉक्टर्स हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जिला- ठाणे. (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.

संपादक – सुरेश त्रिपाठी

- इलाहाबाद : उमेश शर्मा ☎ 094155 08625
- गोरखपुर : विजय शंकर ☎ 094508 80000
- भुसावल : शेख सत्तार ☎ 093706 15244
- रतलाम : मुकेश सिंह ☎ 094274 84069
- वड़ोदरा : विजय नायर ☎ 098240 16464

कानूनी सलाहकार
एड. एम. एस. ठक्कर, कल्याण, एड. प्रकाश ताहिलरामानी, मुंबई, एड. राजेश मुधोलकर, ठाणे, एड. कमलेश त्रिपाठी, रायबरेली, एड. बी. एच. वास्वानी, भोपाल, एड. एम. पी. दीक्षित, पटना.
किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद का न्यायिक क्षेत्र कल्याण होगा.

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618
POST Regd. No. Tech/47-1542/MBI/2015-2017